



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 149]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 3 अप्रैल 2017—चैत्र 13, शक 1939

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 03 अप्रैल 2017

क्र. एफ 7-6-2017-उन्तीस-1.—राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की धारा 28(1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत उल्लेखित योजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में सामाजिक अंकेक्षण करने/कराने हेतु राज्य शासन एतद्वारा नगरीय क्षेत्रों में नगर निगम/नगर पालिका/नगर परिषद् एवं ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों को प्राधिकृत करता है.

2. उक्त निकायों द्वारा प्रत्येक त्रैमास में अपने क्षेत्राधिकार में अधिनियम अंतर्गत संचालित योजनाओं का ग्राम सभा/वार्ड सभा के माध्यम से सामाजिक अंकेक्षण कराया जाएगा.

3. स्थानीय निकायों द्वारा सामाजिक अंकेक्षण का प्रतिवेदन जिला शिकायत निवारण अधिकारी (कलेक्टर) के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा.

4. स्थानीय निकायों द्वारा अंकेक्षण का निष्कर्ष निकाय के सूचना पटल पर भी प्रदर्शित किया जाएगा.

उक्त के विधिवत् अभिलेख संधारण का दायित्व संबंधित स्थानीय निकाय का होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. के. चन्देल, उपसचिव.